बदलते परिदृश्य में पाकिस्तान में अमेरिका व चीन की बढ़ती भूमिका : भारत की चुनौतियाँ

अमित कुमार सिंह, शोध छात्र (एस0आर0एफ0), राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

ABSTRACT

भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के सामने अनेक सामरिक एवं सामयिक समस्याएँ नित नए रूप में उभरती रहती हैं। बदलती विश्व व्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य में भारतीय सुरक्षा की आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों के कारण रक्षा परिवेश व रक्षा चिंतन के समक्ष नए आयाम उत्पन्न हो गए हैं। किसी भी देश की सुरक्षा व रक्षा सरकार से कहीं अधिक उसके इतिहास, भूगोल एवं भू–राजनीति पर निर्भर करती है। विश्व में भारत की भू–सामरिक स्थिति विशेष महत्वपूर्ण है। इस स्थिति के आधार पर भारत पश्चिम में गोल्डन क्रीसेण्ट (स्वर्णिम चन्द) और पूर्व में गोल्डन ट्राइंगल (स्वर्णिम त्रिभुज) के मध्य में है। हिन्द महासागर के मध्य में स्थित भारत इस क्षेत्र की प्रमुख एवं आर्थिक शक्ति तो है ही तथा जनसंख्या की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की जनसंख्या दक्षिण एशिया के अन्य छः देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है और जीवन की लगभग सभी गतिविधियों में इसकी यही स्थिति है। भारत के पड़ोसी देश बाहर की ताकतों का फायदा उठाते रहे हैं और उन्हें आमंत्रित करते रहे हैं। यही कारण है कि भारत आज शांति, अमन और नवीन विश्व–व्यवस्था के स्थान पर नित नए संघर्ष की ओर लगातार व्याप्त अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रहा है।[1]

एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में अपने उदय के पश्चात् पाकिस्तान दक्षिण एशिया में सदैव एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उपस्थित रहा है। वह भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, अमेरिकी महाकूटनीति का ताकतवर मोहरा तथा भारत को उलझाए रखने के लिए कुटिल चीन का मुख्य अस्त्र रहा है। पाकिस्तान ने सदैव ही अमेरिका व चीन, दोनों से ही आर्थिक व सामरिक सहायता व रणनीतिक शक्ति प्राप्त की है।

9/11 की घटना के बाद तालिबान व अल–कायदा के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंधों में थोड़ा परिवर्तन आया। अफगानिस्तान को अपने नए गढ़ के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहे अमेरिका के लिए पाकिस्तान की आतंकवाद परस्त नीति कठिनाइयाँ बढ़ाने वाली सिद्ध हो रही थी। 9/11 के बाद अमेरिका ने भारत के वैश्विक महत्व को भी अनुभव किया तथा इन दोनों ही कारणों से अमेरिका की एशिया नीति में भारत अधिक महत्त्वपूर्ण कारक बनकर उभरा। यद्यपि अमेरिका अपने अनेक स्वार्थों व विवशताओं के कारण पाकिस्तान को समर्थन देने की नीति को पूर्णतः परिवर्तित नहीं कर सका है। वहीं अमेरिका की भारत से बढ़ी नजदीकी ने सशंकित पाकिस्तान को चीन के पाले में पूर्णतः चले जाने हेतु प्रेरित किया है।[2]

हाल के वर्षों में चीन और पाकिस्तान की मैत्री अपने घनिष्ठतम् रूप में आती देखी गई है। भारत की एक विश्व शक्ति के रूप में उदय की सम्भावनाओं से चीन अन्दर ही अन्दर भयभीत है, और इसी कारण उसने पाकिस्तान से अपने संबंधों को उच्चतम स्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया है, ताकि भारत के विरूद्ध एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया जा सके। सी0पी0ई0सी0 (चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर) जो कि चीन की महत्वाकांक्षी 'वन बेल्ट, वन रोड' परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है, पाकिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव को स्पष्टतः परिलक्षित करता है। सी0पी0ई0सी0 (चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर) के माध्यम से चीन ने वस्तुतः पाकिस्तान को पूरी तरह अपना बन्धक बना लिया है। साथ ही इस परियोजना के माध्यम से वह पाकिस्तान में अपनी उपस्थिति को स्थायी कर लेने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के साथ चीन की मित्रता का एकमात्र कारक भारत–विरोध ही रहा है और आज भी यही कारक इस मित्रता को और अधिक दृढ़ बना रहा है।[3]

चीन के द्वारा पाकिस्तान के समुद्र तट पर स्थित ग्वादर बन्दरगाह का विकास तथा संवर्धन उसके समुद्री हितों की पूर्ति के साथ–साथ अरब–सागर में भारत पर निगाह बनाए रखने की नीति का ही अग्रसरण है। इसके अतिरिक्त चीन, पाकिस्तान को कई नए

(चश्मा I & II) परमाणु रिएक्टर बनाने में भी सहायता दे रहा है। पाकिस्तान की प्रक्षेपास्त्र तकनीक तो पूरी तरह चीन से आयातित है ही। पाकिस्तान की समर्पणवादी नीति के कारण चीन अब उसे अपना परोक्ष उपनिवेश बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। हालांकि स्वयं पाकिस्तान में, विशेषकर गुलाम कश्मीर में चीन की हरकतों का विरोध जनसाधारण द्वारा किया जा रहा है।

चीन के अतिरिक्त अमेरिका भी पाकिस्तान को अपनी दक्षिण– एशियाई तथा अफ़गानिस्तान नीति के परिप्रेक्ष्य में साधे रखना चाहता है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रम्प के शासनकाल में भी वर्ष 2017 तक में अमेरिकी प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता जारी रखने की घोषणा की गई। आतंकवाद के मुद्दे पर भी अमेरिका, पाकिस्तान को ज़ुबानी हिदायतें देने के अतिरिक्त कुछ ठोस कदम उठाता नहीं दिखा। वास्तव में ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन तथा कुछ सीमा तक पश्चिम एशिया पर भी दृष्टि जमाए रखने के उद्देश्य से पाकिस्तान, अमेरिका के लिए अब भी महत्वपूर्ण बना हुआ है।[4]

पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति ही भारत–विरोध पर आधारित है। अमेरिका व चीन जैसी महाशक्तियों के लगातार समर्थन तथा उनसे प्राप्त सहायता का उपयोग पाकिस्तान ने सदैव भारत के विरूद्ध ही किया है। चीन द्वारा पाकिस्तान में अपनी पैठ बढ़ाए जाने के फलस्वरूप गुलाम कश्मीर को लेकर भारतीय दावे पर संकट की स्थिति आती प्रतीत हो रही है। क्योंकि सी0पी0ई0सी0 का एक प्रमुख मार्ग गुलाम कश्मीर से ही होकर गुज़रता है, और चीन सी0पी0ई0सी0 के ही बहाने गुलाम कश्मीर में अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। इसमें सैन्य उपस्थिति भी शामिल है। ज़ाहिर है, चीन की परियोजना भारतीय सम्प्रभुता पर गम्भीर आघात करती है, और इसी कारण भारत ने प्रत्यक्ष रूप से चीन की ओबोर (वन वेल्ट, वन रोड) परियोजना का विरोध करते हुए इससे स्वयं को पृथक रखा है।

पाकिस्तान में ग्वादर बन्दरगाह के विकास के बहाने चीन ने इस क्षेत्र में अपने नौसैनिक अड्डे बनाने का कार्य प्रारंभ किया है, जो कि भारत को घेरने की उसकी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति का ही हिस्सा है। यद्यपि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अपना नियंत्रण स्थापित करके चीन की इस चाल को लगभग निष्प्रभावी कर दिया है। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रमुख विषय पाक प्रयोजित आतंकवाद है, जिससे भारत दशकों से पीड़ित है। चीन द्वारा संयुक्तराष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किये जाने वाले प्रस्ताव को बार–बार रोक दिये जाने (वीटो किए जाने) के कारण आतंकवाद के विरूद्ध भारत की मुहिम के समक्ष बाधा उत्पन्न हुई है। साफ़ है कि भारत को दबाने के लिए चीन आतंकवाद से भी समझौता करने पर आमादा है, जबकि उसके शिनजियाँग प्रान्त में उइग़र आतंकवाद स्वयं एक समस्या बना हुआ है।[5]

इधर 9/11 के बाद अपने हितों पर आए संकट के कारण अमेरिका ने पश्चिम एशिया व अफ़गानिस्तान में स्थित आतंकवादी समूहों के विरूद्ध कार्यवाही तो की है, परन्तु यह कार्यवाही मात्र उसके अपने हितों के अनुकूल ही क्रियान्वित की जाती रही है। अमेरिका पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी सैन्य कार्यवाही तो करता है, परन्तु केवल उन संगठनों के खिलाफ़ जो उसके लिए ख़तरा हैं। भारत के विरूद्ध सक्रिय आतंकवादी समूहों के विरूद्ध अमेरिका कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाता। आतंकवाद के विरूद्ध यह दोहरा रवैया ही आतंकवाद की जड़ों को और अधिक पुष्ट करता जा रहा है।

यद्यपि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नये साल 2018 के छठे ट्वीट से दक्षिण एशियाई खासकर पाकिस्तानी राजनीति में खलबली मचा दी है। यह ट्वीट बेहद करारा, स्पष्ट और निर्णायक था (पाकिस्तान को आर्थिक मदद बंद करना) और भारत के लिहाज से इस ट्वीट को महत्वपूर्ण माना गया। बहरहाल इधर अमेरिका के रिश्ते जितने ही भारत से बढ़ते गये, पाकिस्तान के रिश्ते उभरती विश्व शक्ति चीन से बढ़ते गये। भारत से अमेरिकी मेलजोल जहाँ पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा था वहीं चीन से पाकिस्तान का मेलजोल अमेरिका को पसन्द नहीं था। अतः अमेरिकी नाराजगी

का मूल कारण पाकिस्तान का धीरे–धीरे चीन, रूस और उत्तर कोरिया के साथ संबद्ध होना है।

चीन की ओवोर नीति और बढ़ती सामरिक सक्रियता ने ही अमेरिका को मजबूर किया है कि वह दक्षिण एशिया क्षेत्र को एशिया प्रशांत क्षेत्र की वृहद दृष्टि से देखे जिसमें चीनी सामरिक प्रभाव को भारतीय केन्द्रीय भूमिका से संतुलित किया जा सके। दरअसल चीन–रूस–पाकिस्तान–उत्तर कोरिया के प्रति चतुष्क (एंडीक्वाड) के जवाब में ही अमेरिका–भारत–जापान–आस्ट्रेलिया का चतुष्क (क्वाड) निर्मित किया गया और ट्रंप का यह ट्वीट ऐंटीक्वाड की एक प्रमुख धुरी पाकिस्तान पर दबाव बनाकर इसी एंटीक्वाड को कमजोर करने की राणनीति है।[6]

चीन और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में अपने प्रभाव का अधिकाधिक विस्तार कोई नई घटना नहीं है। भारत की समस्या यह है कि वह इस परिस्थिति के सापेक्ष अपनी शक्ति में आवश्यक वृद्धि नहीं कर सका है। शक्ति, शक्ति का ही सम्मान करती है, यह सुप्रसिद्ध तथ्य है। अतः प्रत्येक क्षेत्र में बहुआयामी प्रगति भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकती है। 1998 के परमाणु परीक्षणों के पूर्व और पश्चात् भारत के प्रति विश्व समुदाय के दृष्टिकोण में आया परिवर्तन भी इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपतित्व काल में यद्यपि अमेरिका की नीति पाकिस्तान के प्रति कुछ कठोर अवश्य होगी परन्तु चीन अपने महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में भारत के उत्थान को रोकने के लिए पाकिस्तान में अधिकाधिक गहराई तक जड़े जमाने का प्रयास करता रहेगा, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है।[7]

उपर्युक्त परिस्थिति में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कठोर कदम उठाने होंगे। कूटनीतिक व राजनीतिक मंचों पर चीन के विरूद्ध गठजोड़ कायम करने के साथ–साथ पाकिस्तान की आतंकवाद–परस्त नीतियों को विश्व के समक्ष बेनकाब करने

की मुहिम तेज़ करनी होगी। हमें अब पाक प्रायोजित आतंकवाद के अतिरिक्त 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स', ओबोर और सी0पी0ई0सी0 जैसी परियोजनाओं की काट भी ढूँढ़नी होगी।

Reference:

1. डा0 एस0 के मिश्रा, ''राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा'', नई दिल्ली (2006)
2. सहारा समय (साप्ताहिक)–18 अक्टूबर 2005
3. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, 2015–2016
4. Strategic Analysis, New Delhi (July-Sep 2014)
5. A. Alam, "US Military Aid. To Pakistan and India's Security, New Delhi.
6. डा0 श्रीश पाठक, ''दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण'', 5 जनवरी 2018
7. A.J. Tellis, "Stability in South Asia, New Delhi.